शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

dqy i`"B&08

ऋषभ पंत ने क्रिकेट में हादसे का यादगार पल साझा किया

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

एनिमल पार्क को लेकर नया अपडेट

Page-05

राज्यसभा में पीएम मोदी का हमला: कांग्रेस पर तीखे आरोप

गुरुवार को राज्यसभा के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला, जहाँ वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच संसद भवन में हंगामा, नारेबाज़ी और वॉकआउट जैसी घटनाएँ देखने को मिलीं, जो आज की राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बनीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को स्पष्ट रणनीति, विज़न और नीतियों के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी देश के विकास एजेंडा के बजाय केवल आलोचना में व्यस्त रहती है। मोदी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उसके कुछ नेताओं के हालिया बयानों ने समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय के एक सांसद को "गद्दार" कहे जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक मॉडल "झूठ, फ़रेब और परिवारवाद" पर आधारित है और "सबका साथ-सबका विकास" उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने जो विकास और वैश्विक समझौते हासिल किए हैं, वे कांग्रेस की सीमित सोच से कहीं ऊपर हैं। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य जब पीएम मोदी बोल रहे थे, तो उन्होंने जोरदार नारेबाज़ी शुरू कर दी, और कुछ सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया कि वह उम्र का ध्यान रखते हुए बैठकर नारेबाज़ी करें, जिससे यह टिप्पणी संसद में चर्चा का विषय बनी। संसद के बजट सत्र में यह मुठभेड़ पहले से जारी गतिरोध की नई कड़ी है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संसद में प्रश्नों के जवाब देने से बच रही है और लोकसभा में PM के भाषण को रद्द कर देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व अपनी जवाबदेही से भाग रहा है, और इसका असर संसद की कार्यवाही पर पड़ा है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान यह भी कहा कि देश का विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि समाधान भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक प्रगति, व्यापार समझौते और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार यह संकेत हैं कि भारत सही दिशा में अग्रसर है। हालांकि विपक्ष का तर्क

रहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों को टालते हुए केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। इस पुरे घटनाक्रम ने भारतीय संसद में राजनीतिक असहमति और व्यापक बहस की स्थिति को उजागर किया।पीएम मोदी ने भाषण के दौरान यह भी कहा कि देश का विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि समाधान भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक प्रगति, व्यापार समझौते और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार यह संकेत हैं कि भारत सही दिशा में अग्रसर है। हालांकि विपक्ष का तर्क रहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों को टालते हुए केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप कर रही है।यह भी देखा गया कि लोकसभा में पीएम के भाषण को सुरक्षा चिंताओं के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते उनका राज्यसभा में भाषण का समय बढ़ा और विपक्ष का विरोध और बढ़ गया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- **पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस के पास स्पष्ट रणनीति और विज़न नहीं है।**
- **विपक्ष की नारेबाज़ी और वॉकआउट के बीच, मोदी ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की और देश के विकास को रेखांकित किया।**
- **राज्यसभा में भाषण के दौरान राजनीतिक तनाव और आरोप-प्रत्यारोप बढ़े, जिससे बजट सत्र में असहमति का माहौल बना।**
- **पीएम मोदी ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों—इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति—को गिनाते हुए कहा कि देश "नीतिगत स्थिरता" के कारण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।**

अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत — अब BCCI के कामकाज में सीधा हिस्सा ले सकेंगे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिससे वह अब बोर्ड के कामकाज तथा गतिविधियों में सीधा भाग ले सकेंगे। शीर्ष अदालत ने अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन किया है, जिसमें तब उन्हें BCCI से जुड़े कामकाज से दूर रहने का निर्देश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट की बेंच — मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची — ने कहा कि 2017 का "Cease and Desist" आदेश आजीवन प्रतिबंध का इरादा नहीं था, और अनुराग ठाकुर अब बोर्ड की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं बोर्ड के नियम और विनियमों के तहत। अदालत ने यह फैसला 'प्रोपरशनलिटी के सिद्धांत' को ध्यान में रखते हुए सुनाया। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और तत्कालीन BCCI सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटाया था,

क्योंकि कोर्ट ने माना था कि वे 2015 में गठित लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में अवरोध डाल रहे थे। उस दौरान ठाकुर द्वारा आईसीसी को लिखे गए पत्र के कारण अदालत ने नाराज़गी जताई थी और उन्हें BCCI से जुड़े कामकाज से दूर रहने का आदेश दिया था।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने गठबंधन से दूरी बनाई, 294 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

आगामी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बड़ा और स्पष्ट रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह इस बार किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ेगी। यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि पिछले पश्चिम बंगाल चुनावों में गठबंधन करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा पैदा हुई थी, जिसके कारण पार्टी को मजबूत प्रदर्शन करने में मुश्किलें आईं इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने अकेले लड़ने का विकल्प चुना है ताकि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय और

प्रेरित रखा जा सके।कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) और अन्य दलों के साथ किसी भी तरह की सीट-बटोरे की बातचीत सफल नहीं हो पाई है, जिस कारण से गठबंधन की संभावनाओं पर अधिक जोर नहीं दिया गया। इस निर्णय से राज्य की राजनीतिक परिदृश्य में नया समीकरण बन सकता है|

बिहार 2025 विधानसभा चुनाव पर नया मोड़:

सुप्रीम कोर्ट में जन सुराज की याचिका, फिर से चुनाव की मांग तेज

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी ने यह कदम चुनावी प्रक्रिया और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाने के बाद उठाया है। जन सुराज पार्टी की याचिका में मुख्य आरोप है कि राज्य सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू रहने के दौरान मतदाताओं को सीधे 10,000 की राशि ट्रांसफर की, जो चुनाव को प्रभावित करने वाला अवैध भुगतान है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के फायदे वोटरों को चुनाव के ठीक पहले दिए गए और इससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हुई। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे इस तरह के "भ्रष्ट आचार" के खिलाफ कार्रवाई करें और चुनावी परिणाम रद्द करने का आदेश दें। जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि अगर अदालत इन आरोपों को सही पाती है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से मतदान सुनिश्चित किया जाए। जन सुराज पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव से पहले जारी की गई वित्तीय सहायता केवल महिलाओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से नहीं थी बल्कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक रणनीति थी। याचिका में यह तर्क भी शामिल है कि इस तरह की वित्तीय हस्तांतरणों का चुनाव के दौरान होना चुनाव कानून और MCC के खिलाफ है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने रखा जाएगा, जिसमें पार्टी की मांग और चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार किया जाएगा। यदि कोर्ट याचिका को स्वीकार करती है, तो यह बिहार की राजनैतिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। पार्टी की यह कानूनी चुनौती उस पृष्ठभूमि में आई है जब जन सुराज पार्टी 2025 के चुनावों में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने बड़ी संख्या में सीटें जीतीं। इस चुनावी असफलता के बाद पार्टी ने नतीजों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पार्टी का दावा है कि जनता की आवाज़ को न्याय के ज़रिये उठाया जा रहा है और यदि अदालत आवश्यक दिशा निर्देश देती है तो भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और MCC या अन्य आचार संहिता नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। जन सुराज का कहना है कि यह मामला केवल एक चुनाव का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।पार्टी ने यह भी जोर दिया कि अदालत का हस्तक्षेप भविष्य के चुनावों के लिए एक सख्त उदाहरण स्थापित कर सकता है।पार्टी का दावा है कि जनता की आवाज़ को न्याय के ज़रिये उठाया जा रहा है और यदि अदालत आवश्यक दिशा-निर्देश देती है तो भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा एमसीसी या अन्य आचार संहिता नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जन सुराज का कहना है कि यह मामला केवल एक चुनाव का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। पार्टी ने यह भी ज़ोर दिया कि अदालत का हस्तक्षेप भविष्य के चुनावों के लिए एक सख्त उदाहरण स्थापित कर सकता है।

जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को चुनौती दी है और चुनाव रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान महिलाओं को दिए गए ₹10,000 के भुगतान ने चुनाव को प्रभावित किया और यह अवैध प्रक्रिया थी।

भारतवर्ष

आवश्यकता

Tv भारतवर्ष ग्रुप

को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में e रिपोर्टर की। और पॉडकास्ट हेतु टैलेंटेड युवक ,और युवतियों की जो डिजिटल मीडिया में अपना भविष्य और पहचान बनाना चाहते है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपनी सीवी 8601780000 व्हाट्सप्प के माध्यम से भेंजे

AI में भारत की छलांग: माइक्रोसॉफ्ट-गूगल समेत टेक दिग्गजों ने किया अरबों डॉलर का निवेश

पहले भारत में वैश्विक राजस्व पर टैक्स के नियमों को लेकर अनिश्चितता थी, जिससे कंपनियां बड़े पैमाने पर विस्तार करने से कतराती थीं। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि नई टैक्स नीति ने इस डर को खत्म कर दिया है, जिससे कंपनियां अब भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक 'ग्लोबल सर्विस हब' के रूप में देख रही हैं

भारत इस समय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 100 करोड़ से अधिक डिजिटल-साक्षर आबादी अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए दुनिया का सबसे 'हॉट मार्केट' बन गई है। भारत की यह बढ़त केवल आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में घोषित 20 साल के टैक्स हॉलिडे ने विदेशी निवेश के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि यह नीति भारत को एक प्रमुख ग्लोबल एआई हब बनने का ऐतिहासिक अवसर देगी, जहां दुनिया भर की डेटा सेवाओं का संचालन यहीं से होगा। एआई के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए अमेरिकी 'हाइपरस्केलर्स' भारत में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल भारत में $17.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की, जबकि उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी अमेजॉन ने एआई और रोजगार सृजन के लिए $35 बिलियन का बड़ा चेक काटा है। इसी कड़ी में गूगल ने दक्षिण-पूर्वी भारत में डेटा केंद्रों और अंडरसी केबल लिंक के लिए $15 बिलियन का निवेश करते हुए इसे 'अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई हब' घोषित किया है। ये कंपनियां केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं बना रही हैं, बल्कि भारत की विशाल डेटा खपत को भुनाने की तैयारी में हैं, क्योंकि भारत में प्रति स्मार्टफोन मोबाइल डेटा की खपत दुनिया में सबसे अधिक है। कारण हैं- पहला, भारत के नए डेटा-प्राइवेसी नियम जो कंपनियों को भारतीय यूजर्स का डेटा स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा, भारतीयों के बीच जेनरेटिव एआई (Gen-AI) को अपनाने की गजब की रफ्तार। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार, 62% भारतीय एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, जो ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची दर है। हालांकि भारत दुनिया का 20% डेटा पैदा करता है, लेकिन वर्तमान में इसका केवल 3% ही भारत में स्टोर होता है। यही वह अंतर है जिसे भरने के लिए दुनिया भर की डेटा सेंटर कंपनियां भारत की ओर दौड़ रही हैं। पहले भारत में वैश्विक राजस्व पर टैक्स के नियमों को लेकर अनिश्चितता थी, जिससे कंपनियां बड़े पैमाने पर विस्तार करने से कतराती थीं। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि नई टैक्स नीति ने इस डर को खत्म कर दिया है, जिससे कंपनियां अब भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक 'ग्लोबल सर्विस हब' के रूप में देख रही हैं। साथ ही, वैश्विक स्तर पर चल रही 'चाइना+1' रणनीति के तहत मल्टीनेशनल कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाला वर्कफोर्स, इंजीनियरों का विशाल पूल और सहायक सरकारी योजनाएं हैं, जो इसे एआई अनुसंधान के बजाय इसके व्यावहारिक और कम लागत वाले अनुप्रयोगों के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा केंद्र बनाती हैं।

केरल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बारूद से लदा ट्रक जब्त

केरल के पलक्कड़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की खेप बरामद की है। पलक्कड़ मेडिकल कॉलेज के पास एक पिकअप वैन से 100 से अधिक जिलेटिन स्टिक के डिब्बे और 20 से ज्यादा डेटोनेटर के डिब्बे जब्त किए गए हैं। विस्फोटक ले जाने का तरीका इतना शातिराना था कि पुलिस भी दंग रह गई। पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, यह जब्ती बुधवार देर रात की गई। खुफिया जानकारी मिली थी कि राज्य में विस्फोटकों की एक बड़ी खेप लाई जा रही है। इसी आधार पर जब पुलिस ने एक पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा कर वैन को घेरा और तलाशी ली। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान सेंथिल के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने कोयंबटूर से डिब्बे लोड किए थे और उन्हें त्रिशूर में एक खदान में ले जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले ही राज्य में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वाहनों की चेकिंग के दौरान पिकअप वैन को रोका गया। हालांकि, ड्राइवर ने कहने पर भी गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। अब ड्राइवर के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि विस्फोटक को काले पत्थर की खदान के कामों में इस्तेमाल के लिए गुप्त रूप से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल विस्तृत जांच चल रही है।

राज्यसभा में PM बोले-कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला

चीन, अमेरिका, रूस को पछाड़कर इस लिस्ट में आगे निकला भारत,

वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) की तरफ से जारी किया गया Responsible Nations Index 2026 देशों को देखने का एक नया नजरिया पेश करता है. यह लिस्ट किसी देश की ताकत को उसकी अर्थव्यवस्था, सेना या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि इस बात से आंकता है कि वह अपने लोगों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है. आज जब दुनिया भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु संकट से जूझ रही है, तब यह रिपोर्ट उन देशों को सामने लाती है जो न्याय, करुणा और लंबे समय की सोच को प्राथमिकता देते हैं.एक वैश्विक रैंकिंग है, जिसमें 154 देशों का मूल्यांकन किया गया है. यह चार मुख्य आधारों पर देशों को परखता है, जो इस प्रकार है: नैतिक और पारदर्शी शासन. सामाजिक कल्याण और नागरिकों की भलाई. पर्यावरण की सुरक्षा. वैश्विक जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार. यह सूचकांक GDP या सैन्य ताकत जैसे पारंपरिक मानकों से हटकर यह देखता है कि देश अपनी शक्ति का उपयोग कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं. भारत 154 देशों में 16वें स्थान पर रहा है और उसका स्कोर 0.5515 है. भारत ने इस सूची में अमेरिका (66वां) और चीन (68वां) जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है. भारत की यह रैंकिंग स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय प्रयासों और जन-केंद्रित शासन में प्रगति को दर्शाती है. इस लिस्ट में पाकिस्तान 154 देशों की सूची में 90वें स्थान पर है. रूस इस लिस्ट में 96नें स्थान पर है. यह साफ करता है कि देश की असली तरक्की ताकत से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से मापी जानी चाहिए. जो देश अपने नागरिकों, प्रकृति और दुनिया के प्रति ईमानदार हैं, वही भविष्य के लिए बेहतर उदाहरण बनते हैं.

भारत टैक्सी ऐप आज लॉन्च, यात्रियों को 30% तक सस्ता किराया, ओला-उबर से होगी टक्कर

भारत के टैक्सी बाजार में 5 फरवरी को यानी आज एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल, सरकार समर्थित सहकारी स्वामित्व मॉडल पर आधारित कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए शून्य कमीशन और यात्रियों के लिए कम किराए का वादा करता है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च करेंगे। शाह ने X पर एक पोस्ट में भारत टैक्सी को सहकारी क्षेत्र में देश की पहली टैक्सी सेवा बताया और इसे निजी एग्रीगेटरों के विकल्प के रूप में पेश किया, जिसका संचालन ड्राइवरों द्वारा ही किया जाएगा। भारत टैक्सी एक पारंपरिक निजी प्लेटफॉर्म के बजाय एक सहकारी पर आधारित है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह मॉडल ड्राइवरों को मालिकाना हक, संचालन और मूल्य निर्माण के केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य निजी कैब प्लेटफॉर्म द्वारा लिए जाने वाले उच्च कमीशन के लंबे समय से चल रहे शिकायतों को दूर करना है। सहकारी संरचना के तहत, प्रत्येक ड्राइवर, जिसे 'सारथी' कहा जाता है, सहकारी समिति में पांच शेयर रखता है। Ola या Uber के विपरीत, भारत टैक्सी प्रत्येक सवारी पर प्रतिशत-आधारित कमीशन नहीं काटेगी। इसके बजाय, ड्राइवर ऐप का उपयोग करने के लिए रोजाना 30 रुपये का फिक्स्ड एक्सेस शुल्क देते हैं। प्रति-राइड कमीशन न होने से ड्राइवरों की कमाई बढ़ती है और उन्हें प्लेटफॉर्म की सफलता में सीधे हिस्सेदार होने का मौका मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का अनुमान है कि यात्रियों के लिए किराया निजी एग्रीगेटरों द्वारा दिए जाने वाले किराए से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। शून्य कमीशन मॉडल से बचत सीधे यात्रियों तक पहुंचती है, जिससे शहरी कैब बाजारों में मूल्य प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ सकती है।

28 फरवरी को बोत्सवाना से आएंगे 8 चीते, भारत के प्रोजेक्ट चीता को नई मजबूती

मध्य प्रदेश की धरती पर दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से आठ चीते आने वाले हैं। इसके अलावा असम से जंगली भैंसा भी लाकर एमपी में बसाए जाएंगे। दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की है। सीएम ने बताया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर करने के लिए भी चर्चा की गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री चीता प्रोजेक्ट, असम से गैंडे और जंगली भैंसे सहित अन्य वन्य प्राणियों को लाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। बोत्सवाना से 8 चीते लाने की प्रक्रिया पूरी कराने सहित प्रोजेक्ट की मंजूरी सहित अन्य कार्यों को लेकर वे दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई है। मध्य प्रदेश की धरती पर दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से आठ चीते आने वाले हैं। इसके अलावा असम से जंगली भैंसा भी लाकर एमपी में बसाए जाएंगे। दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की है। सीएम ने बताया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर करने के लिए भी चर्चा की गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री चीता प्रोजेक्ट, असम से गैंडे और जंगली भैंसे सहित अन्य वन्य प्राणियों को लाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। बोत्सवाना से 8 चीते लाने की प्रक्रिया पूरी कराने सहित प्रोजेक्ट की मंजूरी सहित अन्य कार्यों को लेकर वे दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में ने बताया कि कि मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

संपादक की कलम से

विकास एक ऐसा व्यापक शब्द है, जो केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और पर्यावरण सहित जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। किसी राष्ट्र की प्रगति को सही मायनों में मापने के लिए केवल जीडीपी या औद्योगिक उत्पादन को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, सामाजिक संरचना और समान अवसरों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है।विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आर्थिक विकास। जब किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोग अपने जीवन स्तर को सुधार पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, औद्योगिक निवेश, नई तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति आर्थिक विकास को तेज करती हैं। लेकिन केवल आर्थिक वृद्धि से ही विकास पूरा नहीं होता। आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए सामाजिक विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण और दलित-पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर समाज के संतुलित विकास में योगदान देते हैं।विकास का तीसरा आयाम है अंतरसंस्कृतिक और नैतिक विकास। किसी भी समाज की प्रगति तभी स्थायी होती है जब उसके नागरिकों में सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य और सहयोग की भावना विकसित हो। केवल भौतिक विकास से समाज में असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।आज का विकास तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के बिना अधूरा है। इंटरनेट, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट शहर, और आधुनिक कृषि पद्धतियाँ समाज और राष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को अवसर देते हैं और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही, विज्ञान और तकनीक स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार लाती है।पर्यावरणीय संतुलन और स्थायी विकास भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विकास केवल उद्योग, निर्माण और शहरों तक सीमित रहेगा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं होगी, तो यह अस्थायी और हानिकारक साबित होगा। सतत विकास के लिए हर कदम पर ऊर्जा की बचत, हरित तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है।अंत में, विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास और सहयोग से ही संभव है। केवल सरकार की नीतियाँ ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी, समाज की जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। जब आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, तभी विकास का वास्तविक अर्थ पूरा होगा।विकास केवल आधुनिक इमारतों या बड़े उद्योगों का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज में सुधार, जीवन की गुणवत्ता, समान अवसर और संतुलित पर्यावरण के साथ एक स्थायी और समग्र प्रगति का नाम है। इसी को अपनाकर हम एक मजबूत, सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव:

राहुल-खारगे ने बनाई कांग्रेस की नई रणनीति,

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं के साथ रणनीति बनाई, जबकि इंडिया ब्लॉक सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन पर अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं की है।

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, राजनीतिक गतिविधियां पश्चिम बंगाल में तेजी से चल रही हैं। इस सन्दर्भ में, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा भारतीय संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कांग्रेस के नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली के 10, राजाजी मार्ग स्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक कार्यालय में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार करना था।पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल इस समय अत्यंत संवेदनशील और गरम है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) है, जिसका नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। टीएमसी को इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और पार्टी नेतृत्व लगातार स्थानीय नेताओं और सांसदों के साथ बैठकें कर उनकी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है।इस बीच, कांग्रेस अपनी स्थिति को मज़बूत करने के प्रयास में है। हालांकि कांग्रेस, ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी के विपक्षी भारत ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन टीएमसी ने अब तक कांग्रेस या किसी भी सहयोगी दल के साथ कोई गठबंधन या चुनावी समझौता करने पर चर्चा नहीं की है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच अभी कोई स्पष्ट चुनावी तालमेल नहीं बन पाया है। इस स्थिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से पार्टी अपने चुनावी अभियान की रणनीति को स्पष्ट कर सकती है और राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की योजना तैयार कर सकती है।इस राजनीतिक परिदृश्य में, भाजपा भी सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सांसदों की चिंताओं को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। भाजपा के सांसद राजू बिस्टा ने बताया कि इस बैठक में नितिन नबीन ने सांसदों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उनके सामने मौजूद मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।राजू बिस्टा ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के सभी सांसद, चाहे वे लोकसभा में हों या राज्यसभा में, इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें पहली बार चुने गए सांसद भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दो घंटे से अधिक समय बिताने और अपनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। यह बैठक पूरी तरह संगठनात्मक थी और इसमें कोई चुनावी निर्णय नहीं लिया गया। यह भाजपा के लिए पहली बार था जब उनके सभी पश्चिम बंगाल के सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह सीधे चर्चा कर पाए। इस बैठक में सांसदों ने अपने व्यक्तिगत और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन सभी मुद्दों पर मार्गदर्शन और सुझाव दिए।राजू बिस्टा ने कहा कि इस बैठक का अनुभव बिल्कुल पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण रहा। सभी सांसदों ने अपनी-अपनी समस्याओं और विचारों को खुलकर साझा किया। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए, जो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी कारण वे भाजपा को अन्य पार्टियों से अलग मानते हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व और सांसदों के बीच इस तरह का खुला संवाद और मार्गदर्शन दुर्लभ है।इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो। पार्टी अपने सभी सांसदों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है और वे हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति मिले।वहीं, कांग्रेस ने भी राज्य में अपनी रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की यह बैठक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी स्थिति का विश्लेषण किया और संभावित गठबंधनों और सहयोगी दलों की भूमिका पर चर्चा की। बैठक के दौरान, यह भी स्पष्ट किया गया कि टीएमसी के साथ फिलहाल कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारियों को पूरी तरह जारी रखेगी और चुनाव में अपनी रणनीति के अनुसार कदम उठाएगी।राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में आने से पहले अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने लक्ष्यों और कार्ययोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने यह भी तय किया कि राज्य के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा।इस पूरे परिदृश्य में यह भी देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं।

राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, खड़गे और नड्डा के बीच तेज बहस

गुरुवार को राज्यसभा में उस समय गरमागरम माहौल देखने को मिला जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संसदीय प्रक्रिया को लेकर एक-दूसरे से तीखी बहस में उलझ गए। यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा भाषण के बाधित होने के एक दिन बाद हुई। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक तब शुरू हुई जब खरगे ने संसद में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बोलने पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई। लोकसभा में हुई बाधा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निचले सदन में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। खरगे ने पूछा कि संसद का अर्थ लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इस तरह सदन कैसे चलाया जा सकता है? राज्यसभा में सदन के नेता नड्डा ने कड़ा जवाब देते हुए इस आरोप को खारिज कर दिया और सदन को संसदीय परंपराओं की याद दिलाई। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने न देने का मुद्दा उठाने पर नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती, मेरे सम्मानित सहकर्मी को यह बात पता होनी चाहिए। नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए हमेशा तत्पर है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के अनुरोध पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौतों पर बयान दिया है। खरगे ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को बोलने नहीं देती, और कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को जंजीरों में जकड़ रखा है, उन्हें बोलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग बंधुआ मजदूर हैं। विपक्ष सत्ताधारी दल की तरह दूसरों को गाली-गलौज या अपशब्द नहीं कहता। मैं बता रहा हूं कि कैसे जनता को बोलने न देकर जनता को कुचल रही है। बहस तेज होते देख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हस्तक्षेप करते हुए मांग की कि खरगे द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द "लिंच" रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले में दखल देते हुए बजट सत्र के दौरान बार-बार हो रही बाधाओं के बीच सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करने का आग्रह किया। रिजिजू ने कहा कि आज सभी सांसद नियमों और परंपराओं के पालन की उम्मीद कर रहे हैं। सभी राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहती, तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन अन्य सदस्य सुनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सदन के नियमों का पालन नहीं किया।

पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव आयोग का निर्देश, 9 फरवरी तक अनुपालन के आदेश

भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनाव संबंधी निर्देशों की कथित अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने एक कड़ा पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार को आगाह किया है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। अब आयोग ने राज्य सरकार को इन निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन के लिए 9 फरवरी 2026 तक की अंतिम समय सीमा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद पहले जारी किए गए कई निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। आयोग ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), दो सहायक ईआरओ (एईआरओ) और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में आयोग ने पांच अगस्त 2025 और दो जनवरी 2026 को भेजे गए अपने पत्रों का भी उल्लेख किया। आयोग ने यह भी कहा कि बशीरहाट-2 की एईआरओ और प्रखंड विकास अधिकारी सुमित्रा प्रतिम प्रधान को निलंबित नहीं किया गया है, जबकि उन पर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से 11 अतिरिक्त एईआरओ की अनधिकृत तैनाती का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 25 जनवरी 2026 के पत्र के जरिए 48 घंटे में अनुपालन करने के लिए कहा गया था। यह 21 सितंबर 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा 31 मई 2023 को जारी आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 27 अक्टूबर 2025 को जारी उसके निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद तीन मतदाता सूची पर्यवेक्षकों अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे के तबादले अब तक रद्द नहीं किए गए हैं। इस संबंध में 27 जनवरी 2026 को भेजे गए पत्र में 28 जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था। आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी चिंता जताई और कहा कि ये उसके निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

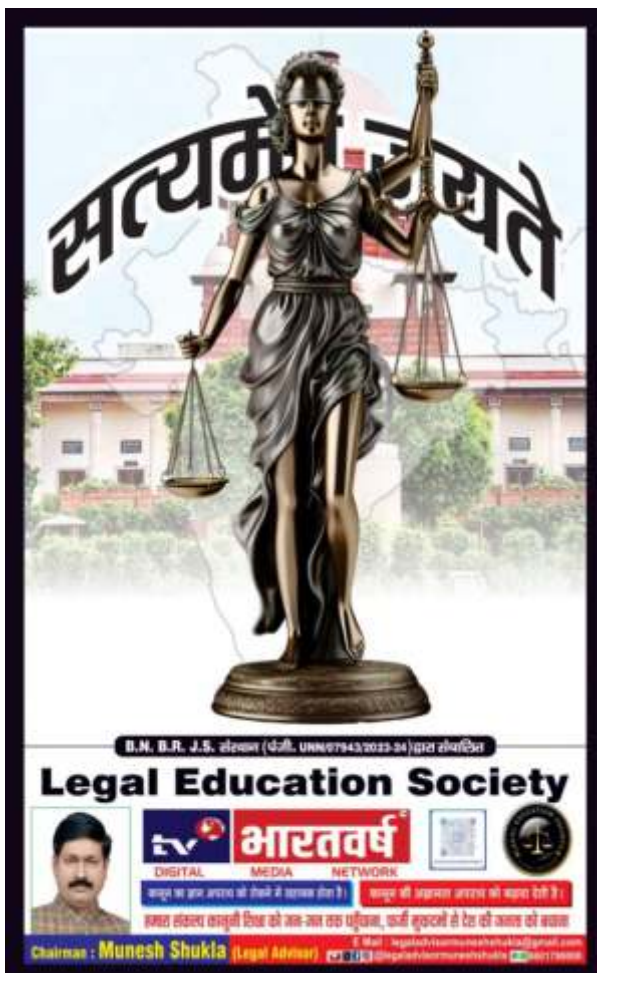

UPSC ने कड़ा कदम उठाया:

अब सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा पर ब्रेक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 को लेकर ऐसे बदलाव किए हैं, जो आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं की पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और अनुशासित बनाने वाले हैं. हर साल लाखों युवा UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं और IAS, IPS, IFS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का सपना देखते हैं. हालांकि, अब यह रास्ता पहले से थोड़ा अलग और ज्यादा स्पष्ट नियमों के साथ तय किया गया है. 4 फरवरी 2026 को जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में UPSC ने सेवा आवंटन, दोबारा परीक्षा देने के नियम और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई बड़े और सख्त फैसले लिए हैं. खासतौर पर IPS से जुड़ी व्यवस्था को लेकर आयोग ने साफ कर दिया है कि अब बार-बार ऑप्शन बदलने की गुंजाइश नहीं होगी. इन नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो उम्मीदवार किसी सेवा में चुने जा चुके हैं, वो गलत तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग न करें और योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिल सके. UPSC के नए नियमों के अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार का चयन पहले ही IPS (Indian Police Service) में हो चुका है, तो वह CSE 2026 के जरिए दोबारा IPS का विकल्प नहीं चुन सकेगा, यानी अब IPS में चयन होने के बाद उसी सेवा के लिए फिर से प्रयास करना संभव नहीं होगा. यह नियम खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, जो रैंक सुधारने के लिए बार-बार परीक्षा देते थे. आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो उम्मीदवार पहले से ही IAS (Indian Administrative Service) या IFS (Indian Foreign Service) में कार्यरत हैं, वे अब सिविल सेवा परीक्षा में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर कोई उम्मीदवार मेन्स परीक्षा से पहले IAS या IFS में नियुक्त हो जाता है, तो उसे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी. UPSC ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है, जो CSE 2025 या उससे पहले किसी सेवा में चयनित हो चुके हैं. ऐसे उम्मीदवारों को अपने बचे हुए अटेम्प्ट्स यूज करने के लिए 2026 या 2027 में एक अंतिम अवसर दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी. यह मौका सिर्फ एक बार के लिए होगा. जो उम्मीदवार 2026 में ग्रुप A सेवा में चयनित हो जाते हैं, लेकिन फिर से UPSC परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी नियम बदले गए हैं. अब ऐसे उम्मीदवारों को अपने विभाग से यह अनुमति लेनी होगी कि वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं. अगर कोई उम्मीदवार न ट्रेनिंग जॉइन करता है और न ही छूट लेता है, तो उसका 2026 का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. अगर वही उम्मीदवार 2027 में फिर से सफल होता है, तो उसे दोनों में से सिर्फ एक सेवा चुननी होगी, दूसरी सेवा अपने आप रद्द मानी जाएगी. UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए अब AI आधारित फेसियल रिकग्निशन और आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है. अब उम्मीदवारों को एक नए चार-चरणों वाले ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह पूरा सिस्टम आधार से पूरी तरह जुड़ा होगा. इससे फर्जी पहचान, डुप्लीकेट आवेदन और परीक्षा में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.

पाकिस्तानी PM बोले- बांग्लादेश के साथ खड़े रहना सही फैसला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार को सही और सोचा-समझा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है। एक फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने X पोस्ट में भारत से मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। उसके बाद ICC ने PCB से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। उसके बाद से PCB का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सरकार फैसला नहीं बदलने वाली है। सरकार की बैठक के बाद शरीफ ने कहा- 'हमने T20 वर्ल्ड कप पर बिल्कुल साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।' शरीफ ने कहा- 'हमने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है और हमें पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना चाहिए।' पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला बांग्लादेश के सपोर्ट में लिया। क्योंकि, ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया था। बांग्लादेश सुरक्षा का हवाला देकर अपने मैच भारत की बजाए श्रीलंका में कराने की मांग कर रहा रहा था। यह पूरा विवाद मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने के बाद शुरू हुआ। BCCI ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में रहमान को भारतीय लीग से हटा दिया था।

मीराबाई चानू ने रचा इतिहास,

वेटलिफ्टिंग में तोड़ डाले तीन-तीन राष्ट्रीय रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने क्रिकेट में हादसे का यादगार पल साझा किया: भगवान कुछ सिखाना चाहते थे...'

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से पहले आजतक के खास कार्यक्रम 'सलाम क्रिकेट' दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की तैयारियों पर मंथन किया. इस कार्यक्रम में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी हिस्सा लिया. पंत फिलहाल इंजरी के चलते क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पेट की मांसपेशियों में गंभीर चोट लग गई थी. ऋषभ पंत ने इस दौरान उस गंभीर कार हादसे को याद किया, जिसके चलते वो काफी दिनों तक एक्शन से दूर रहे. 30 दिसंबर 2022 को पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पंत ने उस हादसे को लेकर कहा कि वो समय उनके लिए काफी बुरा था और भगवान उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे. पंत ने ये भी कहा कि उन्होंने डिस्लोकेट हुए पैर को खुद ठीक करके लगाया था. पंत ने पिछले इंग्लैंड दौरे के दौरान पैर में लगी चोट से जुड़ी दर्दनाक कहानी

को भी बयां किया. पंत ने बताया कि कैसे वो फ्रैक्चर के बावजूद मैदान पर बैटिंग करने उतर गए थे. ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर लगी चोट को लेकर कहते हैं, 'फर्स्ट इनिंग्स उस समय काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि सीरीज पूरी तरह खुली हुई थी. कोई कसर बाकी नहीं रखना है, ये हमारा सोचने का प्रोसेस था. चोट लगी तो दर्द के अलावा माइंड में कुछ भी नहीं आया. हॉस्पिटल गया, लोगों से बातचीत की. दूसरी इनिंग्स में हमने कमबैक किया, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स के दौरान हम गेम में पीछे थे. आपको पता है कि फुल फ्रैक्चर है. मेरा लास्ट फिंगर पूरी तरह स्नैप हो गया था.

SC ने अनुराग ठाकुर पर 9 साल पुराना बैन हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के पूर्व प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर से लाइफ टाइम बैन हटा दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को अपने 9 साल पुराने फैसले को बदला है। उसमें ठाकुर को बोर्ड से दूर रहने को कहा गया था। अब वे भारतीय क्रिकेट के संचालन में बोर्ड के कामकाज में शामिल हो सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि उन पर जिंदगी भर का प्रतिबंध लगाना न तो सही था और न ही इसका कोई इरादा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा- 'यह आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने का सही मामला है।' बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि अनुराग ठाकुर पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। साल 2017 में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने की वजह से अनुराग ठाकुर को पद से हटाया गया था। लोढ़ा कमेटी के नियमों में आयु सीमा और सरकारी पद जैसे कई कड़े प्रावधान शामिल थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जनवरी, 2017 के फैसले के निर्देश 3 और 4 पहले ही वापस ले लिए गए थे। मौजूदा आवेदन केवल उन पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित था। अनुराग ठाकुर के वकील ने कहा कि यह प्रतिबंध लगभग 9 साल से लागू था और इसे जारी रखने से गंभीर कठिनाई होगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी कर उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने उनसे लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से बचने के लिए ICC से एक लेटर के जरिए दखल मांगने के संबंध में उन पर लगाए गए झूठी गवाही के आरोपों पर जवाब देने को कहा था।

टी-20 वर्ल्डकप, पाकिस्तान से मैच पर सूर्या बोले-हम तैयार हैं

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर चल रहीं चर्चाओं के बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया का रुख स्पष्ट कर दिया। गुरुवार को मुंबई में कैप्टन्स डे के दौरान सूर्या ने कहा कि भारत मैच खेलेगा। सामने वाली टीम नहीं खेलना चाहती तो यह उनकी मर्जी है। मुंबई में बातचीत के दौरान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के कोच ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर के असर को लेकर बात की। उन्होंने कहा, गंभीर ने टीम के भीतर जो माहौल बनाया है, वह काफी सकारात्मक है। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी सहज रहता है। भारत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। वहीं, श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी में मुकाबले होंगे। कोलंबो में आर प्रेमदासा और सिंहला स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। टीम इंडिया मुंबई, दिल्ली, कोलंबो और अहमदाबाद में ग्रुप स्टेज के मैच खेलेगी।

हमारा माइंडसेट बिल्कुल साफ है। हमने खेलने के लिए मना नहीं किया है, उधर से मना किया गया है। ICC ने मैच का शेड्यूल तय किया है और हम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे टिकट बुक हैं और दिल्ली के बाद हम कोलंबो जा रहे

राजस्थान में भैरू बाबा के दरबार में लगेगा 651 क्विंटल चूरमे का भोग

JCB से बन रहा महाप्रसाद

कोटपूतली में भैरू बाबा के भंडारे में जेसीबी मशीन से 651 क्विंटल चूरमा बन रहा. इसका भैरू बाबा को भोग लगेगा. फिर 4 लाख लोगों के बीच इसका वितरण किया जाएगा. यहां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व दिल्ली सहित देश के कोने-कोने से लोग पहुंचेंगे.

हिमांशु शर्मा, आजतक

यहां जेसीबी से बनाया जा रहा 651 क्विंटल चूरमा (Photo - ITG)

राजस्थान के कोटपूतली बहरोड जिले में इन दोनों एक ऐसे मेले की तैयारी चल रही है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.

30 जनवरी को अरावली के पहाड़ियों के बीच बने भैरू बाबा के मंदिर में 651 क्विंटल चूरमें का भोग लगाया जाएगा. इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. जेसीबी मशीन से चूरमा मिलाने व बनाने का काम चल रहा है. साथ ही इस काम में थ्रेसर मशीन की मदद से चूरमे को पीस गया है. ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन व ट्रक सहित अन्य मशीनों की मदद से चूरमा को मिलाने व एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

कोटपूतली बहरोड जिले में प्रसिद्ध छापाला भैरूजी का मंदिर है. इसमें 17वें लक्की मेले का आयोजन चल रहा है. 30 जनवरी को लगने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु भैरू बाबा के दर्शन के लिए आते हैं. इस मेले में इस बार चार लाख लोगों के लिए चूरमा बनाया जा रहा है. करीब 5000 से ज्यादा लोग रात दिन मिलकर इस प्रसाद को तैयार कर रहे हैं. इस महाप्रसाद को जेसीबी मशीन और थ्रेसर की मदद से तैयार किया जा रहा है. ⊙

चीन में अब मशीन चेक कर रही होमवर्क

दुनिया में AI का इस्तेमाल जितनी तेजी से बढ़ रहा है, चीन ने उसे सीधे क्लासरूम तक पहुंचा दिया है. अब वहां बच्चे होमवर्क तो खुद बनाते हैं, लेकिन उसे चेक करने की जिम्मेदारी किसी टीचर की नहीं AI की होती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखता है कि कैसे एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क बच्चों की हैंडराइटिंग स्कैन करते ही गलतियां पकड़ लेते हैं, सेकंडों में ग्रेड दे देते हैं. ⊙

आज की तस्वीर

बर्फबारी ने तोड़ा 200 साल का रिकॉर्ड

रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले दो सौ वर्षों की सबसे भारी बर्फबारी ने जनजीवन ठप कर दिया. सड़कों, इमारतों और पार्कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई, जिससे यातायात और दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं. मौसम विभाग के मुताबिक यह ऐतिहासिक बर्फबारी तापमान में तेज गिरावट और बदले मौसमी पैटर्न का नतीजा है, जिसने शहर को पूरी तरह सफेद कर दिया. (Photo: AFP)

स्टारबक्स के CEO को मिला प्राइवेट जेट का फ्री पास

1600 किमी दूर से रोज ऑफिस पहुंचता है शख्स

सोचिए, आपका ऑफिस घर से 10-20 किलोमीटर दूर हो तो भी रोजाना आने-जाने में आधा दिन निकल जाता है. लेकिन क्या कोई शख्स रोज 1600 किलोमीटर का सफर सिर्फ ऑफिस पहुंचने के लिए कर सकता है? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन स्टारबक्स के नए CEO ब्रायन निकोल के लिए यह रोजमर्रा की रुटीन बन चुका है और अब इसका पूरा खर्चा कंपनी खुद उठाएगी, चाहे वे ऑफिस जाएं या कहीं और उड़ान भरें. ब्रायन निकोल कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट में रहते हैं, जबकि स्टारबक्स का हेडक्वॉर्टर वॉशिंगटन के सिएटल में है. दोनों शहरों के बीच की हवाई दूरी करीब 1600 किमी है. ऐसे लंबे सफर को आसान बनाने के लिए कंपनी ने उन्हें ऐसा 'सुपर-पावर' दिया है, जिससे रोजाना आने-जाने का सफर अब किसी झंझट जैसा नहीं रहेगा, यानी कंपनी का प्राइवेट जेट. कंपनी ने अपने CEO को प्राइवेट जेट का अनलिमिटेड इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. पहले ब्रायन निजी यात्रा के लिए जेट का उपयोग तो कर सकते थे, लेकिन उस पर 250,000 डॉलर की सालाना कैप लगी थी. ⊙

एनिमल पार्क को लेकर नया अपडेट, विलेन से लेकर शूटिंग तक के संदीप रेड्डी वांगा ने खोले राज

फिल्म एनिमल 2023 में आई थी और फैंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था. फिल्म ने 900 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. फिल्म का दूसरा पार्ट एनिमल पार्क भी आना है. अब मेकर्स ने दूसरे पार्ट को लेकर अपडेट दिया है. फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि मिड-2007 से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी. फिल्म एनिमल का जापान में प्रीमियर हुआ. जापानी ऑडियंस से वर्चुअल इंटरेक्शन में संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल पार्क के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'एनिमल पार्क जल्द ही शुरू होगी. वो फिलहाल अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं. उसके बाद एनिमल पार्क पर काम करेंगे. इस बार फिल्म में ज्यादा एनिमल होंगे. क्योंकि अजीज भी एक और एनिमल होगा. दो भाईयों के बीच इस बार लड़ाई देखने को मिलेगी, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं. इसीलिए एनिमल पार्क परफेक्ट टाइटल है. शूटिंग मिड-2007 से शुरू होगी.' संदीप रेड्डी वांगा ने ये कंफर्म किया कि एनिमल पार्क में रणविजय सिंह के रोल में रणबीर कपूर होंगे. वहीं अजीज फिल्म में विलेन होगा, इस रोल को भी रणबीर ही प्ले करेंगे. रणबीर कपूर भी इस दौरान वीडियो कॉल में थे. उन्होंने फिल्म में वापसी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाई. इस बार वो रणविजय के रोल के साथ-साथ अजीज का भी रोल प्ले करने वाले हैं. रणबीर फिल्म में डबल रोल में होंगे. रणबीर ने कहा, 'मैं संदीप के सेट पर वापस लौटने के लिए एक्साइटेड हूं. ये पहले वाली फिल्म के आगे की कहानी है. पहले पार्ट को शूट करते वक्त संदीप के दिमाग में दूसरे पार्ट की कहानी क्लियर थी. मेरे लिए एक एक्टर के तौर पर ये इंस्पायरिंग है. मैं और संदीप इसके बारे में बात करते रहते हैं.'

2 साल में यूपी में 1 लाख लोग लापता, लखनऊ हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित पेश होने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत आंकड़े तलब किए, जिसमें 1,08,300 लापता और केवल 9,700 पाए गए। न्यायालय ने अधिकारियों की लापरवाही गंभीर बताया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को लेकर दर्ज स्वतः संज्ञान याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों से पूरे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सभी आंकड़े और रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। इस अवसर पर न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया।दरअसल, चिनहट क्षेत्र के निवासी विक्रमा प्रसाद ने न्यायालय को अवगत कराया कि उनका बेटा जुलाई 2024 में गुम हो गया था। उन्होंने चिनहट थाने में अपने बेटे के लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई ठोस या संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इस तथ्य को सामने रखते हुए, न्यायालय ने याची की सूचना पर उचित कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी देने का आदेश अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को दिया।आदेश के अनुपालन में, अपर मुख्य सचिव ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 तक की अवधि के दौरान पुलिस के समक्ष दर्ज लापता होने की सूचनाओं का विवरण दिया। शपथ पत्र के अनुसार, इस अवधि में कुल 1,08,300 लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा, शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि इन सभी लापता व्यक्तियों में से केवल 9,700 लोगों का ही पता चल पाया है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रदेश में लापता व्यक्तियों के मामलों में संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर्याप्त और संतोषजनक नहीं है।न्यायालय ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति गंभीर है और यह दिखाती है कि गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी का पालन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए इसे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों के संदर्भ में शीर्षक के साथ जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। आज हुई सुनवाई इसी जनहित याचिका के तहत हुई।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या और उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपने प्रियजन को खोजने के लिए पुलिस के पास जाता है, तो उसे त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद होती है। हालांकि, प्रस्तुत आंकड़े यह बताते हैं कि इस क्षेत्र में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। 1,08,300 लोगों के लापता होने और केवल 9,700 का पता चल पाने की स्थिति यह दिखाती है कि वर्तमान व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं।इस अवसर पर न्यायालय ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी संबंधित विभाग गुमशुदा व्यक्तियों की सूची और उनकी तलाश के प्रयासों की सही जानकारी उपलब्ध कराएँ। इसके अलावा, पुलिस विभाग से यह भी अपेक्षित किया गया कि वे लापता व्यक्तियों के मामलों में नियमित और सक्रिय कार्रवाई करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों पर निरंतर निगरानी और उचित कार्रवाई आवश्यक है, ताकि नागरिकों का विश्वास प्रशासन और कानून व्यवस्था पर बना रहे।इस तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है कि लापता व्यक्तियों के मामलों में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और उन्हें तुरंत, प्रभावी और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। इस सुनवाई के अगले चरण की अगली तारीख 23 मार्च तय की गई है, जब अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जानकारी और कार्यवाही की स्थिति प्रस्तुत करने को कहा गया है।

लखनऊ में कुत्तों ने महिला को दौड़ाकर नोंचा

लखनऊ में आवारा कुत्तों ने एक महिला को दौड़ाकर नोंचा। महिला के पैर में गहरे जख्म हो गए। उनका उपचार चल रहा है। मामले की नगर निगम में शिकायत हुई है। घटना 4 फरवरी, बुधवार को इस्मालगंज द्वितीय वार्ड की शिवपुरी कॉलोनी, कमता में हुई। महिला की पहचान सोना देवी के रूप में हुई है। आज, गुरुवार को घटना की CCTV फुटेज सामने आई है। उसमें कुत्ते महिला को दौड़ाकर नोंचते दिख रहे हैं। शिवपुरी कॉलोनी, कमता में सोना देवी परिवार के साथ रहती हैं। वह 2 फरवरी को मेडिकल स्टोर से लौट रही थीं। इस दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया। वह डरकर चिल्लाती हुई भागीं, लेकिन कुत्ते दौड़ाते रहे। कुछ दूरी पर वह सड़क पर गिर गईं। कुत्तों ने उन्हें नोंचना शुरू कर दिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास की महिलाएं और अन्य लोग आ गए, तब कुत्तों ने उन्हें छोड़ा। इसके बाद एक अन्य कुत्ता दूसरी ओर से उन्हें काटने आया, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। सोना देवी ने दैनिक भास्कर को बताया- मैं घर से दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई थी। वहां पर दवा नहीं मिली। पैदल ही घर लौट रही थी। रास्ते में दो कुत्ते सा े रहे थे। इस दौरान मेरी दो सहेलियां मिल गईं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरिद्वार जा रहे हैं। इसी बीच कार के नीचे बैठे कुत्ते ने उन्हें दौड़ा लिया। वह डरकर भागीं। रास्ते में सो रहे दोनों कुत्ते भी उनके पीछे पड़ गए। तीनों कुत्तों ने करीब 30 मीटर तक दौड़ाया। मैं सड़क पर गिर गई। तीनों ने मिलकर मुझे नोंचा। गनीमत रही कि मेरी सहेलियां और अन्य लोग आ गए तो कुत्ते भागे।

लखनऊ में SIR को लेकर विवाद, मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटने का आरोप

लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों के नाम SIR प्रक्रिया में काटे जाने की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गांव के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सरोजनीनगर क्षेत्र के फर्रूखाबाद चिल्लावां गांव के रहने वाले दशरथ कुमार नामक व्यक्ति ने फॉर्म-7 भरकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के अनुसार, दशरथ कुमार ने बीएलओ रमजान अली को आवेदन देते हुए कई लोगों को मृत या गांव का निवासी न होने का दावा किया था। बीएलओ द्वारा संबंधित लोगों को फोन कर सत्यापन किए जाने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बूथ पर पहुंचे और अपने नाम काटे जाने पर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि दशरथ कुमार खुद चिल्लावां गांव का स्थायी निवासी नहीं है, बल्कि गांव का दामाद है और वह अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। इसके बावजूद उसने एक ही समुदाय के लगभग 100 से अधिक लोगों के नाम कटवाने के लिए

फॉर्म-7 जमा कर दिया, जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी पहले से ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं, आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद सुहैल ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए फॉर्म-7 देने वाले दशरथ कुमार पर सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि दशरथ कुमार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वह मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम एसआईआर सूची से कटवाना चाहता है। इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी व्याप्त है। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ मेयर ने मृतक आश्रितों को सौंपे ज्वाइनिंग लेटर

नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में गुरुवार को मेयर सुषमा खर्कवाल ने मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मेयर सुषमा खर्कवाल ने कुल 13 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें शेखर, रागिनी, विकास भारती, बीनू, रितिक गहरवाल,अवनीश कुमार, पिन्की, आकाश कुमार भारती, सुभाष धानुक,नीरज कुमार, शिवांशू भारती,काजल और शिवम भारती शामिल हैं। इन सभी मृतक आश्रितों को सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया है। मेयर ने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामना देते हुए कहा कि नगर निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को नौकरी देना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का माध्यम है। महापौर ने सभी नवनियुक्त कर्मियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरा किया गया है। इस पहल से न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

लखनऊ में 60 फीट ऊंचे पेड़ से लटकता मिला शव

लखनऊ के चारबाग इलाके में एक युवक ने 60 फीट ऊंचे पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटकता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हाइड्रोलिक मशीन मंगाकर करीब 5 घंटे मशक्कत करके शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। पहचान नहीं होने के कारण शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया।

पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नाका पुलिस को सूचना मिली एक अज्ञात युवक स्टेशन के पीछे की तरफ पेड़ से लटक गया है। इसके बाद टीम ने शव उतारने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा। इसके लिए टीम को हाइड्रोलिक मशीन लगानी पड़ी। जिसकी मदद से शव उतारा गया। युवक कैसे पेड़ के ऊपर पहुंचा इसकी जानकारी की जा रही है। वहीं तस्वीर की मदद से पुलिस पहचान में जुटी हुई है।

यूपी में इलेक्ट्रिक बसों का किराया तय

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निगम ने बुधवार को इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के लिए नई किराया दरें तय कर दीं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय कुछ समय पहले गठित की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने इस पर औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। परिवहन निगम के की माने तो साधारण इलेक्ट्रिक नॉन एसी बस का किराया 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। जनरथ एसी (3×2) सेवा के लिए 1.64 रुपए, जनरथ एसी (2×2) के लिए 1.94 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एसी स्लीपर इलेक्ट्रिक बस का किराया 2.59 रुपए और वाल्वो और स्कैनिया जैसी प्रीमियम एसी बसों का किराया 2.86 रुपए प्रति किलोमीटर रखा गया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक तय किराया दरों में यात्रियों की सुविधा के नाम पर छह से सात प्रतिशत सेस और मामूली टोल टैक्स भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में टिकट की अंतिम कीमत तय दर से थोड़ी अधिक होगी। फिलहाल लखनऊ से प्रयागराज के लिए 24 और लखनऊ से आगरा के लिए चार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें सिटी बस सेवा के तौर पर भी चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में लखनऊ से अन्य शहरों के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन निगम मुख्यालय के अनुसार लखनऊ से प्रयागराज की दूरी करीब 205 किलोमीटर है। इस दूरी पर साधारण इलेक्ट्रिक बस का मूल किराया 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 266.50 रुपये बनता है। इसमें सेस और टोल टैक्स जोड़ने के बाद यात्रियों को कुल 302 रुपये चुकाने होंगे। वहीं इसी दूरी के लिए एसी

इलेक्ट्रिक बस का किराया सभी टैक्स मिलाकर करीब 349 रुपये तय किया गया है। निगम ने साफ किया है कि प्रदेश में जल्द ही 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पूरी तरह सुचारु किया जाएगा। इससे यात्रियों को न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल सफर मिलेगा, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा भी अपेक्षाकृत किफायती हो सकेगी।

यूपी में कैंसर इलाज का व्यापक नेटवर्क, लखनऊ से वाराणसी तक विस्तार

अब उत्तर प्रदेश के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों की ओर रुख करने की मजबूरी नहीं रह गई है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में जिस तरह से कैंसर उपचार से जुड़ा स्वास्थ्य ढांचा विकसित हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी और सुलभ कैंसर उपचार व्यवस्था वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। लखनऊ से वाराणसी तक फैला कैंसर ट्रीटमेंट नेटवर्क न सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, बल्कि अब बिहार और नेपाल जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं।योगी सरकार के बहुस्तरीय और योजनाबद्ध प्रयासों के चलते कैंसर की स्क्रीनिंग से लेकर सुपर स्पेशियलिटी इलाज और आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर सुविधाएं सशक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट विजन के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिल रहा है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में समय, संसाधन और विशेषज्ञता सबसे अहम होते हैं, और उत्तर प्रदेश ने इन तीनों ही मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है।लखनऊ के चक गजरिया क्षेत्र में स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान आज अत्याधुनिक कैंसर उपचार का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। यह संस्थान 220 बेड की क्षमता के साथ आधुनिक रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रहा है। यहां मरीजों को न केवल इलाज की उच्च गुणवत्ता मिल रही है, बल्कि समय पर जांच और उपचार की व्यवस्था ने उनकी जीवन प्रत्याशा को भी बेहतर किया है। यह संस्थान प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले मरीजों के लिए भी भरोसेमंद केंद्र बन गया है।इसी तरह वाराणसी में स्थापित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल पूर्वांचल क्षेत्र के लिए जीवनरेखा साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों से शुरू किए गए ये संस्थान टाटा मेमोरियल मॉडल पर कार्य कर रहे हैं, जहां इलाज, शोध और प्रशिक्षण को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इन संस्थानों ने पूर्वांचल के लाखों लोगों को बड़े शहरों में भटकने से राहत दिलाई है।लखनऊ और वाराणसी के बीच विकसित यह कैंसर उपचार नेटवर्क रेफरल सिस्टम, विशेषज्ञ परामर्श और तकनीकी सहयोग के माध्यम से मरीजों को त्वरित और प्रभावी इलाज उपलब्ध करा रहा है। गंभीर मामलों में मरीजों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में समन्वित तरीके से भेजा जाता है, जिससे इलाज में देरी न हो और सर्वोत्तम विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। इस नेटवर्किंग मॉडल ने कैंसर उपचार की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर ओपीडी, सफल सर्जरी और उपचार के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और कैंसर जैसे जटिल रोगों का इलाज अब सरकारी संस्थानों में भी प्रभावी ढंग से संभव हो पा रहा है।कैंसर के शुरुआती चरण में पहचान को बढ़ावा देने के लिए जिला गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लिनिक के माध्यम से स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन क्लिनिकों में कैंसर के लक्षणों की शुरुआती जांच की जा रही है, जिससे

बीमारी का समय रहते पता चल सके और इलाज की सफलता दर बढ़ाई जा सके। विशेष रूप से महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना और कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में करना है, ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि धन के अभाव में किसी भी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए। इसी सोच के तहत आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है।इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में सामने आया है। बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीजों को सीधे अस्पतालों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ताकि इलाज के दौरान धन की कमी बाधा न बने। यह व्यवस्था खासतौर पर उन मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य प्रमुख संस्थानों में बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी विभाग को भी सशक्त किया गया है,

उन्नाव में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस भीषण एक्सीडेंट में एक दंपति और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा एक ट्रक चालक की लापरवाही और भागने की कोशिश के कारण हुआ। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, यह हादसा बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे सोहरामऊ थाना क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भल्ला फार्म के पास हुआ। हसनगंज क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि लखनऊ से कानपुर जा रहे एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश में गति बढ़ा दी, जिसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इस दोपहिया वाहन पर सवार दंपति और उनके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कुमार ने बताया कि यह परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था। मृतकों की पहचान उन्नाव जिले के अजगैन गांव के निवासी वीरेंद्र (35), उनकी पत्नी रितु (33), उनकी नौ वर्षीय बेटी और छह वर्षीय बेटे के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर देर रात ट्रकों की अनियंत्रित गति और ओवरटेकिंग की समस्या पहले भी कई जानलेवा हादसों का कारण बन चुकी है। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद सड़क पर गश्त बढ़ाने और ओवरस्पीडिंग पर लगाम लगाने की मांग की है।

लखनऊ में युवा कल्याण अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न

लखनऊ में जिला कल्याण अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न की FIR दर्ज की गई है। अधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति को शादी में 93 लाख और थार गाड़ी दी गई थी, लेकिन वे और दहेज मांग रहे थे। पीड़िता निकिता तिवारी के अनुसार, 14 फरवरी 2025 को बीआर पैलेस, आईआईएम रोड लखनऊ में हिंदू रीति-रिवाज से शिवाकांत द्विवेदी के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद वह जानकीपुरम विस्तार स्थित ससुराल पहुंचीं, जहां पति शिवाकांत द्विवेदी और सास-ससुर ने कम दहेज का ताना देना शुरू कर दिया। निकिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले 25 लाख रुपए नकद और फॉर्च्यूनर कार की मांग की। कुछ समय बाद यह मांग बढ़ाकर 50 लाख रुपए नकद और नई फॉर्च्यूनर कर दी गई। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और बार-बार अपमानित किया गया। निकिता ने तहरीर में बताया कि पति शिवाकांत द्विवेदी का मृदाली पांडे नाम की महिला से अवैध संबंध है। आरोप है कि दोनों साथ-साथ कई जगह घूमे और होटलों में भी रुके। जब इस बारे में सवाल किया गया तो पति और ससुराल पक्ष ने हिंसक व्यवहार किया और धमकियां दीं।

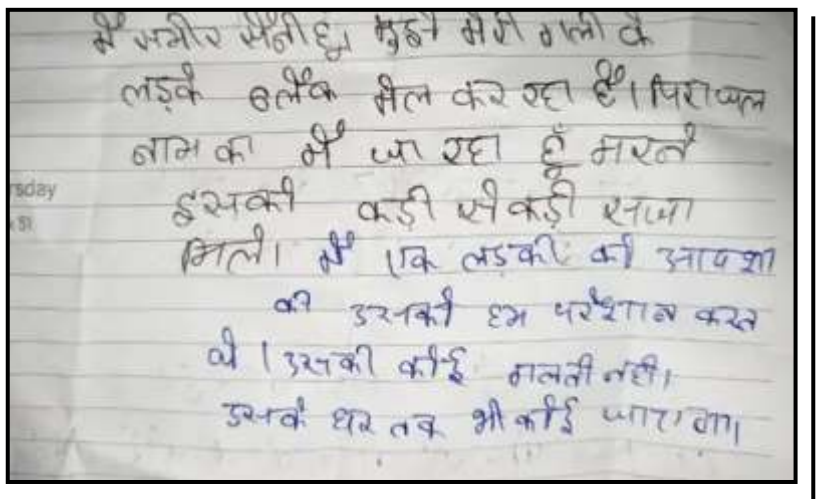

कानपुर में 10वीं का छात्र ट्रेन के आगे कूदा, नोट में लिखा- उस लड़के को सजा मिले

कानपुर में 10वीं के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को छात्र के आईपैड के कवर में सुसाइड नोट मिला। नोट में लिखा- मैं समीर सैनी हूं, मुझे मेरी गली का एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। मैं मरने जा रहा हूं। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। पूरी गलती मुर्गी (मोहल्ले के एक लड़के का नाम) की है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर छात्र की शिनाख्त की। घरवालों ने बताया कि बुधवार शाम वह कोचिंग के लिए घर से निकला था। मगर वह कोचिंग नहीं पहुंचा। गुरुवार सुबह वह पोस्टमार्टम पहुंचे। घटना पनकी थाना क्षेत्र की है। शास्त्री नगर निवासी अनिल सैनी दादा नगर स्थित प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार में उनकी पत्नी अनीता, बड़ी बेटी गुनगुन और 17 साल का बेटा अनिकेत उर्फ समीर सैनी था। अनिकेत विजय नगर स्थित बृज पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल का छात्र था।

चचेरे भाई वैभव ने बताया कि समीर घर से करीब एक किमी. दूर कोचिंग पढ़ने जाता था। वह रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोचिंग पढ़ने जाता था। बुधवार शाम वह कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था।

मगर वह कोचिंग नही पहुंचा। टीचर ने फोन कर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद घरवालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसके दोस्तों को फोन कर जानकारी की। रिश्तेदारी में फोन किया। मगर उसका कहीं पता नहीं चला। घरवाले उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। जहां उन्हें जानकारी मिली कि एक लड़का ट्रेन से कटा है।

गुरुवार सुबह घर वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जहां कपड़ों और समीर के अधजले हाथ से उसकी पहचान हुई। पनकी जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि पनकी धाम स्टेशन के पास युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था। जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को अनिकेत का आईपैड मिला। जिसके कवर में एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था।

सुसाइड नोट को घरवालों ने पुलिस को सौंप दिया है। घरवालों ने बताया कि जनवरी महीने में स्कूल में एक फंक्शन था। समीर ने साथ में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। जिसे उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। पोस्ट का स्क्रीन शॉट लेकर इलाके का एक किशोर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह धमकी दे रहा था कि उसे और उस लड़की को बदनाम कर देगा। लड़की के घरवालों को बता देगा कि लड़की और समीर के बीच लव अफेयर है। घरवालों ने बताया कि समीर उस लड़के की धमकी से डर गया था। बताया कि आरोपी किशोर समीर को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रहा था।

मगर समीर ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। ब्लैकमेल से परेशान होकर ही उसने सुसाइड किया है।

मैं समीर सैनी हूं, मुझे मेरी गली के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं मरने जा रहा हूं। इसको (किशोर) कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने एक लड़की के साथ फोटो खिंचाई थी, उस लड़की को भी वह परेशान कर रहा था। जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं है। उसके घर तक गया। सब गलती मुर्गी (किशोर का घर का नाम) की है। मेरे फोन में 3 आईडी हैं। हम जा रहे हैं। यहां से बहुत दूर। हम फिर बोल रहे, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि घरवालों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम भिजवाया था।

आनंद घाट पर आरती स्थल का निर्माण फिर शुरू

उन्नाव जिले के आनंद घाट पर बनारस की तर्ज पर विकसित किए जा रहे गंगा आरती स्थल के निर्माण कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगभग सात महीने के लंबे अंतराल के बाद यह काम दोबारा शुरू हुआ है। जुलाई माह में गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण निर्माण कार्य को रोकना पड़ा था, क्योंकि पूरा निर्माण स्थल जलमग्न हो गया था। अब गंगा का जलस्तर सामान्य होने और परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद कार्यदायी संस्था ने दोबारा मशीनें और श्रमिक लगाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ बीते वर्ष 6 मार्च को किया गया था। सदर विधायक ने विधिवत भूमि पूजन कर इस आरती स्थल की आधारशिला रखी थी। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। योजना के अंतर्गत आनंद घाट पर करीब 25 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा भव्य आरती स्थल विकसित किया जा रहा है। इसके निर्माण से उन्नाव को धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।आरती स्थल की यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की निगरानी में संचालित की जा रही है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लखनऊ की एक कार्यदायी संस्था को सौंपी गई है। संस्था ने 15 जून से आरती स्थल के लिए पिलर पाइलिंग का कार्य शुरू किया था। शुरुआती चरण में काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा।जलस्तर में वृद्धि के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने लगा और 4 जुलाई को स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरा निर्माण स्थल गंगा के पानी में डूब गया। ऐसे में श्रमिकों की सुरक्षा को देखते हुए निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ा। इसके बाद करीब सात महीने तक गंगा का जलस्तर ऊंचा बना रहा और पानी उतरने के बाद भी मिट्टी के पूरी तरह सूखने का इंतजार करना पड़ा। इसी वजह से परियोजना लंबे समय तक ठप पड़ी रही।अब गंगा का जलस्तर सामान्य हो जाने और जमीन की स्थिति अनुकूल होने के बाद कार्यदायी संस्था ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में पिलर और आधार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है, ताकि आगे के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। निर्माण स्थल पर मशीनें लगाई गई हैं और श्रमिकों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।इस बीच पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप पांडे ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।निरीक्षण के दौरान संदीप पांडे ने कहा कि आनंद घाट पर आरती स्थल के निर्माण से श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। यहां नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे श्रद्धालुओं को बनारस की तर्ज पर धार्मिक अनुभूति प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना उन्नाव के धार्मिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आरती स्थल के बन जाने से आनंद घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नियमित गंगा आरती के आयोजन से न सिर्फ धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर में धर्मांतरण का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग

उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से धर्मांतरण के दबाव और यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अब उसकी शादी टूटने की कगार पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कथित सपा नेता आमिर जैदी समेत चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता के अनुसार, साल 2013 में पिता के निधन के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी. इसी का फायदा उठाकर आमिर जैदी ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोप है कि आमिर ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार गलत काम भी किया. मामला तब और बिगड़ गया जब 18 सितंबर 2025 को युवती के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी.

इसकी भनक लगते ही आमिर अपने सहयोगियों, शनि उर्फ सनी अब्बास, रिजवी, और राजा उर्फ अख्तर अंसारी के साथ मिलकर युवती पर हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा. आरोपियों ने युवती को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो रिश्तेदारों को भेजे और होने वाले ससुराल वालों तक भी आपत्तिजनक सामग्री और चिट्ठियां पहुंचाईं. इन बाधाओं के बावजूद, लड़के पक्ष ने 29 अक्टूबर 2025 को सगाई की रस्म पूरी की. आगामी 14 फरवरी को शादी होनी तय है, जिसे रुकवाने के लिए आरोपी अब युवती के होने वाले पति और ननद को सीधे तौर पर धमका रहे हैं.

CM योगी ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश

यूपी में चाइनीज मांझे से हुई मौत अब हादसा नहीं, हत्या मानी जाएगी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद अब सरकार का रुख सख्त हो गया है। यूपी में पहले ही चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। हालांकि, लगातार इसका उपयोग होता रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद अब सरकार का रुख सख्त हो गया है। यूपी में पहले ही चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। हालांकि, लगातार इसका उपयोग होता रहा है। ताजा वारदात के बाद सीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जातई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे आपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित हैदरगंज पुल के पास बुधवार की शाम बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब की गर्दन में मांझा फंस गया था। शोएब कुछ समझ पाते इसके पहले ही मांझे से उनकी गर्दन की नसें कट गई। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी और अचेत होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोर्ट और एनजीटी ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद चोरी-छिपे यह बिक रहा है। प्रतिबंध के बावजूद मांझा की बिक्री पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सकता है। बीएनएस की धारा 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा या जुमार्ना हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और पाच साल की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी चाइनीज मांझा लोगों की जान ले रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र का हाल ऐसा है कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए दिए गए आदेश-निर्देश हवा में हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने का ही परिणाम है कि हर साल मकर संक्रांति के समय कई लोगों की गर्दन कट जा रही है। घटना होने के बाद पुलिस जागती है, फिर आदेश जारी होते हैं। कार्रवाई का दिखावा होता है। इसके बाद चुप्पी हो जाती है। फरवरी 2024 में पर्यावरण विभाग की तरफ से प्रतिबंध की राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित की गई। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए। उसके बाद भी यह सभी आदेश-निर्देश हवा में ही रहे। जानलेवा मांझे के निर्माण से लेकर उपयोग तक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित है, पर सच्चाई यह है कि पुलिस को छोड़ बाकी विभाग सुस्त पड़े हैं। वन विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को जैसे कुछ पता ही नहीं है कि शासन ने उन्हें भी जिम्मेदारी दी है।

UP: कौशल प्रतियोगिता युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर, रोजगारोन्मुख और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) द्वारा इंडिया स्किल्स कॉम्पीटिशन 2025-26 के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं का भव्य सम्मान समारोह बुधवार को कौशल विकास मिशन मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया. इस अवसर पर 20 विभिन्न स्किल ट्रेड्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 40 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम एवं मिशन निदेशक पुलकित खरे ने विजेताओं को सम्मानित किया. प्रत्येक स्किल ट्रेड से दो विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कौशल, समर्पण और परिश्रम से प्रदेश का नाम रोशन किया.प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने विजेता प्रतिभागियों से संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, प्रतियोगिता यात्रा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली तथा उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक, रोजगारोन्मुख एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे आयोजनों से युवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित होती है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का अवसर मिलता है.

योगी सरकार में गुप्तारघाट के पर्यटन विकास को मिली रफ्तार, थिएटर जल्द खुलेगा

अयोध्या में गुप्तारघाट का वैभव पुनः लौट रहा है. पर्यटन विकास तेजी से हो रहा है. योगी सरकार की रामराज्य की परिकल्पना के अनुरूप आने वाले दिनों में गुप्तारघाट का हर एक नजारा त्रेता युग को जोड़ता दिखेगा. क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल इस महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर तीसरे चरण का विकास कार्य अब अंतिम दौर में पहुंच गया है. विशेष रूप से यहां बन रहा ओपन एयर थियेटर संभवतः होली तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस थियेटर के साथ रावण वध, हनुमान और जटायु की भव्य मूर्तियां भी तैयार हो चुकी हैं, जो रामायण की भावना को जीवंत रूप से दर्शाएंगी. गुप्तारघाट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मान्यता है कि भगवान राम ने इसी घाट से जल समाधि ली थी और यहां अंतिम बार सरयू नदी में प्रवेश किया था. राम भक्तों के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र है. योगी सरकार ने इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है. पहले दो चरणों में बड़े पैमाने पर विकास हो चुका है, जिसमें घाट का सौंदर्यीकरण, वॉटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, आधुनिक पार्क, योग-ध्यान केंद्र आदि शामिल हैं. अब तीसरे चरण में कुल 1833.63 लाख रुपये की लागत से अंतिम छोर का काम चल रहा है. यह परियोजना पर्यटन विभाग की है. यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है. अयोध्या परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. परियोजना में कुछ विलंब हुआ है, क्योंकि कार्यों में बढ़ोतरी की गई. मूल लक्ष्य से दो महीने पीछे चल रही यह परियोजना अब फरवरी 2026 में पूरी हो जाएगी. होली के आसपास या होली तक (मार्च 2026) यह ओपन एयर थियेटर और पूरा परिसर श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. आगामी दिनों में गुप्तारघाट न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और मनोरंजन का भी प्रमुख केंद्र बन जाएगा. योगी सरकार का फोकस अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने पर है. राम मंदिर के बाद गुप्तारघाट का यह विकास राम नगरी की चमक को और बढ़ाएगा.

यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा

योगी सरकार की ओर से वन व वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में बढ़ाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। सरकार के प्रयासों का असर है कि उत्तर प्रदेश में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है. राज्य में प्रतिवर्ष दो बार सारस की गणना की जाती है. प्रदेश के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए. पिछले साल हुई गणना में प्रदेश में सारसों की संख्या 19,994 थी। राज्यव्यापी गणना में इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस मिले. 10 वन प्रभागों में यह संख्या 500 से अधिक रही. प्रदेश में शीतकालीन गणना कार्यक्रम में 10 हजार नागरिकों द्वारा भाग लिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु-पक्षी व पर्यावरण प्रेम जगजाहिर है. 2017 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने विभाग को राज्य पक्षी सारस के संरक्षण पर विशेष जोर दिया. 2023 में प्रदेश में 19,196 सारस मिले. 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 19,994 हो गई. अब इस शीतकालीन सत्र में प्रदेश में कुल सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई है. सारस की शीतकालीन गणना में 10 प्रभागों में इनकी संख्या 500 से ऊपर रही। इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस पाए गए। मैनपुरी में 2899, औरैया में 1283, शाहजहांपुर में 1078, गोरखपुर में 950, कन्नौज में 826, कानपुर देहात में 777, हरदोई में 752, सिद्धार्थनगर में 736 तथा संतकबीर नगर वन प्रभाग में 701 सारस पाए गए।